

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2015/4993-5003 जयपुर,दिनांक: 22/4/15
जिला कलेक्टर,(सहायता)
जैसलमेर (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में खरीफ खराबा रिपोर्ट के आधार पर घोषित अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2041,2046 दिनांक 10.04.2015, 2053 दिनांक 11.04.2015, 3413 दिनांक 17.04.15 एवं 3761 दिनांक 18.04.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1(1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/ 2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है अभाव संवत् 2071 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वीकृत पंजीकृत गौशालाएँ, जिनकी अवधि राज्य आपदा मोचन निधि में अनुमत 90 दिवस पूर्ण कर ली गई है उन पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 17.04.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की निम्न पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान जारी दिनांक से 30 दिवस तक स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	तहसील का नाम	पंजीकृत गौशाला का नाम	गौशालाओं में संधारित पशुओं की संख्या		
			बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1	जैसलमेर	श्री विष्णु गौशाला समिति कबीर बस्ती	260	40	300
2		जन्त गौशाला जेसुराणा	170	35	205
3		श्री बादलनाथ गौशाला संस्थान म्यालामठ म्याजलार	424	200	624
4		श्री पन्नोधाय गौ सेवा समिति जैसलमेर	80	20	100
5		गौ सेवा संस्था दरबारी का गांव	40	10	50
6		वुन्दावन गौशाला जामडा	160	40	200
7		श्री जगदम्बा सेवा समिति गौशाला	15556	5455	21011

		भादरिया			
8		श्री मामड़ियाई जी राष्ट्रीय समन्वयक सेवा समिति सांगड़	1800	58	1858
9		चानणगढ़ गोशाला चानणगढ़	485	43	528
10		सालेह फकीर विकास सोसायटी केहर फकीर की ढाणी	245	70	315
11		सुखाणी गौशाला भम्भारा	317	41	358
12		तनोटाराय गौशाला संस्थान खुईयाला	250	30	280
13		स्व. नांगोदस्खाँ सेवा विकास समिति गौशाला मूंदरडी	227	23	250
		योग:-	20014	6065	26079

इसी अनुक्रम में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे:-

1. अनुदान दर:-

गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/- रुपये तथा छोटे पशु हेतु 25/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. पशु आहार:-

(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ कमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि कमशः 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50 रुपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा कय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. निरीक्षण मापदण्ड :-

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:-

क. स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/ पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/ पं. समिति



4. **अनुदान की देयता:-**

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्ट्रों का संधारण कराया जावें।:-

क. खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर

ख. पशुओं का रजिस्टर

ग. दैनिक खर्च रजिस्टर

घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. **भुगतान:-**

गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. **पशु संख्या:-**

गौशालाओं के पशुओं की संख्या सक्षम अधिकारी, कम से कम उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृति के आदेश समय पर ही जारी किये जा सकें।

7. **पशु संख्या में बढ़ोतरी :-**

विगत वर्षों में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई। उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढ़े हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बढी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सकें।

8. किसी भी संचालक संस्था जिसके माध्यम से पशु शिविर, चारा डिपो या गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव अभाव अवधि में ही प्रेषित करें।

9. यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन पशु शिविरो की अवधि 90 दिन पूर्ण होने पर उन्हीं पशुओं को अन्य संस्था के नाम से या गौशालाओं के माध्यम से नहीं खोले जा रहे हैं। अपनी संतुष्टि के उपरांत ही आवश्यक होने पर ही गौशालाओं की स्वीकृति दी जाये।

10. पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।

11. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित गौशाला के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जायें। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)
12. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
13. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित की जाने वाली गौशालाओं हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक पत्रावलीया खोली जाएगी। एवं इस से सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रजिस्टर खोले जाएंगे। संचालक संस्था के स्तर पर भी पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे।
14. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाली गौशालाओं पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्वत् 2071 में खरीफ फसल खराबों के समय किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग होने का उलेख किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,
21/1/15

शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव